

प्रेषक,

भूपिन्दर कौर औलख
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक ५ नवम्बर, 2015

विषय- राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किये जाने विषयक।

महोदय,

राज्य में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी अवधि दिनांक 30.11.2015 को समाप्त हो रही है, की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये मा० मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अगले चरण में जटिल बीमारियों को भी इस योजना में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित करते हुये योजना का शुभारम्भ दिनांक 01.12.2015 से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- विस्तारित मा० मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के सभी ए०पी०एल० तथा बी०पी०एल० परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु योजना में आयकर दाता तथा राजकीय कर्मचारी/अधिकारी एवं पेंशनरों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने वाले परिवारों में वे सभी परिवार सम्मिलित होंगे जो वर्तमान पॉलिसी में पंजीकृत/कार्डधारक हैं, इसके अतिरिक्त दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 से प्रदेश के सभी ए०पी०एल० तथा बी०पी०एल० परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु उक्त योजना में आयकर दाता तथा राजकीय कर्मचारी/अधिकारी एवं पेंशनरों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4- प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत चिकित्सा लाभ की अधिकतम धनराशि प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹ 50,000/- (रु० पचास हजार मात्र) का बेस कवर पूर्व की भाँति ही रहेगा तथा इसके अतिरिक्त अधिकतम ₹ 1,25,000/- (रु० एक लाख, पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि जटिल रोगों के चिकित्सा लाभ (Critical Cover) हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन स्वरूप निम्नवत होगा :-

1. वर्तमान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भाँति निर्वाचन आयोग द्वारा एकत्रित मतदाताओं के डाटाबेस के आधार पर ही पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
2. वर्तमान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार ही नवीन प्रस्तावित पॉलिसी में भी निर्वाचन आयोग द्वारा एकत्रित मतदाता के डाटा बेस को ही आधार माना जायेगा।
3. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्तमान पॉलिसी के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले समस्त कार्डधारक परिवार स्वतः ही उक्त प्रस्तावित नवीन योजना के पात्र लाभार्थी होंगे।
4. प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लागू होने से 02 माह तक अन्य छोटे हुये परिवारों के पंजीकरण हेतु एक सघन पंजीकरण अभियान चलाया जायेगा, जिसमें ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्त्रियों के माध्यम से पूर्व की भाँति फॉर्म भरकर जमा किये जायेंगे तथा तत्पश्चात् उनका पंजीकरण कर कार्ड मुद्रण किया जायेगा। इसके पश्चात् जनपद स्तर पर स्थापित District Kiosk में आगामी 04 माह के लिये छोटे हुये कार्ड बनाने तथा गलत मुद्रित कार्डों में वांछित संशोधन का कार्य किया जायेगा।

5. नवीन पंजीकृत होने वाले परिवारों से पंजीकरण/कार्ड प्राप्त करने हेतु प्रति परिवार से ₹ 50/- का भुगतान शुल्क के रूप लिया जायेगा।
6. आगामी वर्षों में कार्ड के नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 03 माह पूर्व से ही नवीनीकरण अभियान चलाया जायेगा, जिसके लिये प्रति कार्ड ₹ 30/- का भुगतान देय होगा।
7. पात्र लाभार्थी परिवारों के नवीन पंजीकरण हेतु आशा कार्यकर्ती को वैरिफिकेशन के उपरान्त ₹ 20/- प्रति कार्ड प्रति परिवार मानदेय के रूप में दिया जायेगा।
8. कार्ड के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में दोबारा कार्ड जारी करने हेतु लाभार्थी को एफ0आई0आर0 की मूल प्रति व प्रति कार्ड ₹ 200/- का भुगतान अलग से करना होगा।

● **बीमा कम्पनी का चयन :-**

- (1) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत परिवारों को आच्छादित करने के लिये बीमा कम्पनी का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा तथा निविदा में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को ही आमंत्रित किया जायेगा।
- (2) ब्लॉक स्तरीय पंजीकरण के दौरान (अधिकतम 02 माह) पंजीकृत लाभार्थी परिवारों के संख्या के अनुसार ही बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा तथा अभियान के पश्चात् पंजीकृत परिवारों को प्रीमियम का भुगतान Pro Rata के आधार पर ही किया जायेगा।

5- योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों के पंजीकरण, कार्ड धारकों को लाभ प्रदान करना, क्लेम के भुगतान, शिकायतों के निष्पादन एवं अन्य मामलों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं :-

- (1) वर्तमान में योजना के अंतर्गत आच्छादित समस्त चिकित्सालय पंजीकृत रहेंगे। नए चिकित्सालयों के पंजीकरण हेतु राज्य नोडल एजेंसी द्वारा बीमा कंपनी को सूची प्रदान की जाएगी जिसके पंजीकरण हेतु चिकित्सालयों से त्रिपक्षीय अनुबंध करना होगा। अनुबंध की समस्त शर्तें एवं पंजीकरण की प्रक्रिया संशोधित वर्तमान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों के अनुसार होगी।
- (2) पंजीकृत चिकित्सालयों का निष्कासन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्य नोडल एजेंसी का होगा।
- (3) कार्ड धारक किसी भी पंजीकृत सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हो सकते हैं। सरकारी चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी से किसी भी पूर्व अनुमति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त करने से पूर्व चिन्हित आकस्मिक व्याधियों के अतिरिक्त समस्त दशाओं में बीमा कम्पनी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (4) पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों के लिए बीमा कंपनी को 03 घंटे एवं मैदानी क्षेत्रों के चिकित्सालयों के लिए बीमा कंपनी द्वारा 04 घंटों के अंदर पूर्व अनुमति प्रदान की जाएगी। पूर्व अनुमति के संबंध में निर्धारित अवधि के अंतर्गत कोई सूचना न प्राप्त होने ही दशा में चिकित्सा की अनुमति स्वतः ही मान ली जायेगी।
- (5) समस्त क्लेम जिनकी पूर्व अनुमति प्रदान की जाएगी उनका भुगतान निर्धारित दरों पर 15 दिनों के अंदर चिकित्सालय को करना बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी क्लेम की पूर्व अनुमति को नकारने की दशा में चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी को सूचित किया जाएगा एवं इसकी सूचना राज्य नोडल एजेंसी के जनपद स्तर पर नियुक्त संबंधित अधिकारी को दी जाएगी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार इस विषय में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
- (6) योजना के संचालन के आधिकारिक दायित्व, वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां महानिदेशालय स्थित एम0एस0बी0वाई0 के राज्य नोडल एजेंसी को पूर्व की भांति प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित समस्त

बीमा योजना एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के संयुक्त संचालन के लिये एक पृथक प्रकोष्ठ का गठन किया जाये जिसे समिति के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

- (7) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के सुचारु संचालन के लिये वर्तमान पॉलिसी के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-100/XXVIII-4-2015-58/2014T.C., दिनांक 11.02.2015 के अनुसार पूर्व से ही स्वीकृत ढांचा कार्य करता रहेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ढांचे का विस्तार भी किया जा सकता है। पंजीकरण शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग राज्य नोडल एजेंसी द्वारा, योजना को संचालित करने हेतु प्रशासनिक व्ययभार हेतु उपयोग किया जाएगा।

6- योजना के सुचारु संचालन हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी (नॉन मेडिकल ऑफिसर) नामित किया जायेगा, जो योजना का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-252(P)XXVIII(3)/2015-16, दिनांक 03.11.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय

(भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- 1485 (1)/ XXVIII-4-2015-58/2014 , तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ओबराँय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिवन, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाला मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 एवं 1/नियोजन विभाग ~~एन0आई0सी0~~।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।

